Chief Minister's Information System

General List of Budget Announcements

Sr. No.	Announcement Para / Announcement Description	Action Taken by Dept.	Status
1	286.0.0(2019-2020 (Modified Budget)) (Hon'ble CM Reply on 29/07/2019) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों हेतु संचालित राजकीय छात्रावासों में देय मैस भत्ते को 2 हजार रूपये से बढ़ाकर 2,500 रूपये किया जाएगा।	विभाग द्वारा संचालित अनु0जाति, अनु0जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा विशेष पिछड़ा वर्ग के 805 छात्रावासों में स्वीकृत छात्र क्षमता 38391 तथा 24 आवासीय विद्यालयों के 9784 विद्यार्थी कुल 48175 विद्यार्थियों के लिए चालू बजट सत्र में 2312.77 लाख रूपये के अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होगी। बजट घोषणा केवल अनुसूचित जाति, अनु0 जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है, जबकि विभाग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग तथा विशेष पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिये भी छात्रावास संचालित है। जिसके लिए पत्रावली दिनांक 03.09.2019 को वित्त विभाग को भिजवायी गई वित्त विभाग की आईडी कमांक 161900901 दिनांक 04.09.2019 के द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय को भिजवायी गई।	Task Initiated
2	219.0.0(2019-2020 (Modified Budget)) मदिरा के अवैध व्यवसाय में शामिल परिवारों को मुख्यधारा में लाने एवं उनके कल्याण के लिये 'नवजीवन योजना' प्रारम्भ की थी। इस योजना को और आगे बढ़ाने के लिये 10 करोड़ रूपये का प्रावधान। जिससे अधिक से अधिक परिवारों को लाभान्वित किया जा सकेगा।	मदिरा के अवैध व्यवसाय में शामिल परिवारों को मुख्यधारा में लाने एवं उनके कल्याण के लिये नवजीवन योजना में वित्त विभाग की आई.डी क्रमांक 101903999, दिनांक 29.08.19 द्वारा 10 करोड रूपये की स्वीकृति दी जा चुकी है। नवजीवन योजना में कुल परिवर्तित बजट प्रावधान 373.14 लाख के विरूद्ध जिलो को 353.15 लाख रूपये आवंटन किया जा चुका है।	Task completed
3	134.17.0(2019-2020 (Modified Budget)) प्रदेश में इस वर्ष सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 250 पदों पर भर्तियां की जायेंगी।	**बजट घोषणा के अनुरूप 250 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन** तथा विभागीय पत्र कमांक 4974 दिनांक 05.08.2019 के द्वारा संयुक्त शासन सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान जयपुर को 251 कनिष्क लिपिक के पदों को भरने हेतु अर्थना भिजवायी गयी है। विभाग ने महिलाओं का अलग केडर बनाने के सम्बन्ध में सेवा नियमों में संशोधन की कार्यवाही विभागीय स्तर पर प्रक्रियाधीन है	Task Initiated
4	133.0.0(2019-2020 (Modified Budget)) ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार मगर हुनरमंद युवा पूंजी के अभाव में स्वयं का काम शुरू नहीं कर पाते। 'हुनर का हर हाथ, रहे रोजगार के साथ' इस सोच के साथ, 'मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना' की घोषणा। योजना में एक लाख युवाओं को रू 1 लाख तक का ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा। इसमें RIICO, RFC, SCST/OBC/Minorities	1. अनुजा निगम को 35.00 करोड की अतिरिक्त राज्य गारन्टी एवं बिना रहन जमानत ऋण देने बाबत अनुमोदन हेतु पत्रावली डायरी क्रमांक 263 दिनांक 21.08.2019 के द्वारा संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय–2) को भिजवायी हुई है जो कि अनुमोदित होकर इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है। 2. वित्त विभाग की अनुमोदन की प्रत्याशा में निगम के पत्राक 27107–121 दिनांक 10.10.2019 के द्वारा	Task Initiated

Chief Minister's Information System

General List of Budget Announcements

Sr. No.	Announcement Para / Announcement Description	Action Taken by Dept.	Status
	Finance Corporation के माध्यम से आगामी 5 वर्षों में कुल रू 1 हजार करोड़ के ऋण वितरित किये जायेंगे। योजना के तहत इस वर्ष 25 हजार युवाओं को लाभान्वित किया जायेगा।	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछडा वर्ग के व्यक्तियों हेतु क्रमशः 5000, 5000 व 10000 कुल 20000 व्यक्तियों को लाभान्वित किये जाने के संबंध में जिलों को अतिरिक्त लक्ष्य आवटित किये जा चुके है। साथ ही उक्त तीनों वर्गो हेतु 7000.00 लाख के वित्तीय प्रावधान किया गया है। उक्त योजना संबंधित राष्ट्रीय निगमों से राशि प्राप्त होने पर ही क्रियान्वित किया जाना संभव हो पायेगा।	
5	114.0.0(2019-2020 (Modified Budget)) राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यकों के बीपीएल परिवारों में होने वाले विवाह के वक्त आर्थिक सम्बल देने की दृष्टि से राज्य में 'मुख्यमंत्री कन्यादान योजना' चलायी जायेगी। जिसके तहत पात्र कन्याओं को रू 21 हजार की सहायता हथलेवा के रूप में प्रदान की जायेगी। इस योजना में आठवीं पास वयस्क बालिका ही सहायता की पात्रा होगी। (बजट भाषण दिनांक 10.07.2019) एससी/एसटी, अल्पसंख्यक बालिकाओं की शादी पर जो बीपीएल हैं, उनके हथलेवा के रूप में 21 हजार रूपये देने का तय किया था। अब इसके साथ जितने भी बीपीएल हैं, उन सबकी लड़कियों की शादी पर 21 हजार रूपये दिये जायेंगे। (बजट बहस पर प्रत्युत्तर दिनांक 16.07.2019)	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत पात्र कन्याओं को रू. 21 हजार की सहायता के रूप में पत्रावली माननीय मंत्री महोदय के डायरी क्रमांक 410, दिनांक 28.08.19 द्वारा वित्त विभाग को भिजवाई गई थी जिस पर वित्त विभाग द्वारा की गई टिप्पणी अनुसार पत्रावली पुनः विभागीय आई.डी. BAM 19 Sje 1080000 दिनांक 10.10.2019 को वित्त विभाग को भिजवायी जा चुकी है।	Task Initiated
6	113.0.0(2019-2020 (Modified Budget)) भिक्षावृति एक सामाजिक अभिशाप है। इस कुरीति को दूर करने के लिए सरकार ने 'भिक्षावृति उन्मूलन अधिनियम, 2012' लागू किया था। परन्तु गत सरकार ने इस कुरीति के उन्मूलन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अब अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग करते हुए सबसे पहले जयपुर को भिक्षावृति मुक्त शहर बनायेंगे।	भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों के पुनर्वास करने के लिए संबंधित विभागों/स्वयं सेवी संस्थाओं एवं सामाजिक कार्यकताओं के साथ विचार–विमर्श कर एक कार्य योजना तैयार किये जाने हेतु प्रमुख शासन सचिव महोदय सान्याअवि की अध्यक्षता आयोजित की गयी है। विभागों/स्वयं सेवी संस्थाओं एवं सामाजिक कार्यकताओं के साथ विचार–विमर्श कर एक कार्य योजना तैयार कर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत् विभागीय आई.डी BAM19 Sje 2190000 दिनांक 10.10.2019 को वित्त विभाग को भिजवायी जा चुकी है।	Task Initiated
7	108.0.0(2019-2020 (Modified Budget)) 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पालनहार योजना के लाभार्थियों को आवास सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से एक नवीन आवासीय पालनहार छात्रावास की स्थापना की घोषणा।	आवासीय पालनहार छात्रावास की स्थापना हेतु वित्त विभाग की आई. डी. संख्या 101904290, दिनांक 01.10.19 द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो गई है। पालनहार छात्रावास संचालन किया जाना प्रक्रियाधीन है।	Task Initiated